वेदना का विलाप - रिपोर्ट सारांश

कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के परिवारों पर हुए इस अध्ययन का ख़ास निष्कर्ष यह है – अपने बच्चों के शैक्षिक भविष्य को लेकर ग़रीब मां-बाप बहुत दुखी हैं और वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि लंबे समय की स्कूलबंदी के चलते उनके बच्चों की सिखाई, उनका समाजी-भावनात्मक विकास और आचरण तबाही के कगार तक जा पहुंचे हैं। हमारी जानकारी में, स्कूल खुलने के बाद, माता-पिता के अनुभवों और अनुभूतियों को लेकर हुआ यह पहला अध्ययन है। हम आशा करते हैं कि नीति-निर्माता और प्रशासक अपनी नीतियां व कार्यक्रम बनाते समय ज़मीन पर पैदा हुई इस आपात स्थिति पर इतनी ही गहरी संवेदना के साथ मनन करेंगे।

पाठकों से हमारा आग्रह है कि वे आंकड़ों के साथ-साथ अभिभावकों की अभिव्यक्तियों पर भी ग़ौर फर्माएं। अभिभावकों के सगरे बयान 'वेदना के विलाप' सरीखे सुनायी पड़ते हैं, जो हमारे इस प्रतिवेदन के शीर्षक का निमित्त भी है। अक्सर ऐसी अनुभूतियां, सांख्यिकी और संपादित टेर की जकड़न में सहम-सहम, सिसकियां बनकर रह जाती हैं। यहां यह याद रखना ज़रूरी है कि ये अभिव्यक्तियां उन राज्यों के अभिभावकों की हैं जो तुलनात्मक हिसाब से अगड़े हैं। अब ज़रा इनकी संख्या को स्कूली-उम्र के उन 20 करोड़ बच्चों के अभिभावकों की संख्या से गुणा कीजिये, जिन्हें सच में करीब दो साल तक कोई सार्थक शिक्षा न मिली।

कोई 70-80 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि पढ़ने व लिखने को लेकर उनके बच्चों की क्षमता या तो कम हुई है या फिर वहीं अटक गयी है (या फिर इसका आकलन करने में वे असमर्थ थे)। अभिभावक बच्चों के व्यवहार में आये बदलाव, मोबाइल फोन्स के प्रति उनकी बढ़ती लत के चलते उनकी एकाग्रता और ध्यान में आयी कमी को रेखांकित करते हैं। वे मानते हैं कि बच्चों के समाजी-भावनात्मक विकास में आये इन बदलावों का प्रतिकूल असर उनके शिक्षार्जन पर पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर उनके मत एकदम स्पष्ट हैं – बच्चों ने असल में कुछ न सीखा। हालांकि, सेहत और सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं, तिस पर बच्चों के माता-पिता, कक्षा में व्यक्तिगत उपस्थिति के द्वारा सीखने के लिहाज़ से स्कूलों को अदेर खोले जाने के प्रबल पक्षधर हैं। यही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई के चलते अभिभावकों पर उपकरण और इंटरनेट खरीदने का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा। यह अध्ययन स्कूलबंदी के दौरान हमारी बढ़ती सामाजिक विषमता को भी उजागर करता है – जो माता-पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई-लिखाई का खर्चा उठा सकते थे, उनका मानना था कि महामारी के दौरान भी उनके बच्चों की शैक्षिक प्रगति हुई।

सामाजिक-आर्थिक समूहों में माता-पिता की प्रतिक्रियाओं में अंतर (तेलंगाना):

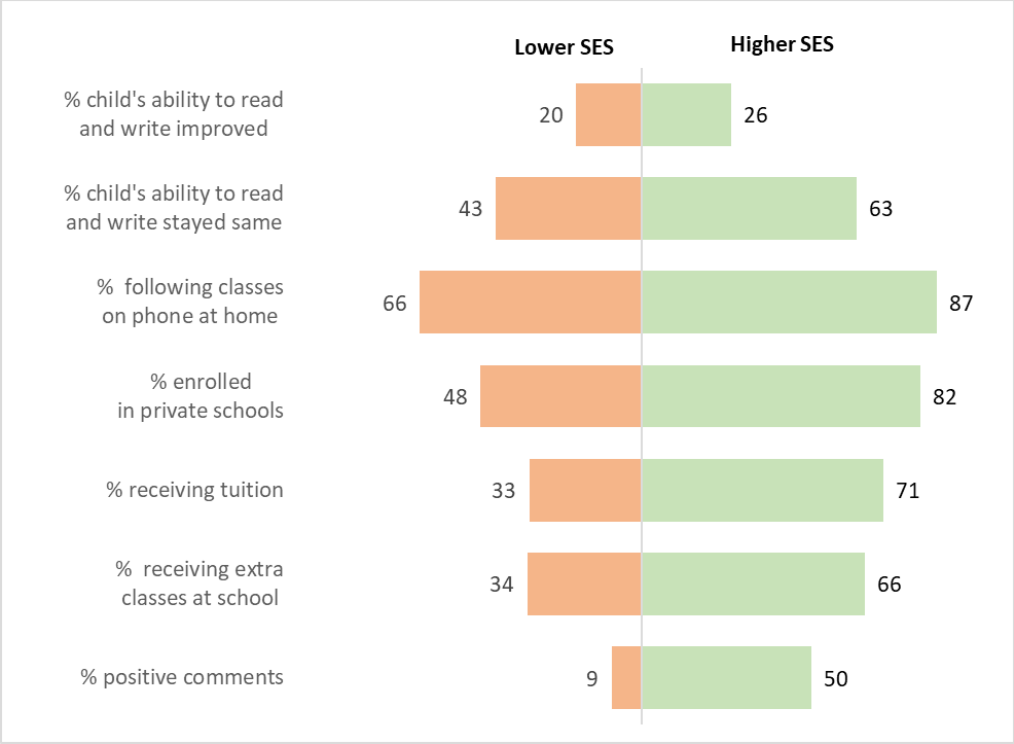

जिन तीन राज्यों के परिवारों का यह सैंपल है, वहां स्कूल-भर्ती के आंकड़े ऐतिहासिक रूप से उच्च-स्तर पर रहे आये हैं, सो स्कूल में बच्चों की औपचारिक नाम-लिखाई भी तुलनात्मक रूप से ऊंचे स्तर पर है। लेकिन, तेलंगाना के हाज़िरी आंकड़े बताते हैं कि पिछले हफ्ते में सिर्फ दो-तिहाई छात्र ही सप्ताह के सभी दिन कक्षा में उपस्थित थे। इन तीनों राज्यों ने दोपहर का खाना

और पाठ्यपुस्तकें देना भी सुनिश्चित किया है। हमारा सर्वे बच्चों के साथ फिर से जुड़ने वाले तमिलनाडु के अभिनव सामुदायिक कार्यक्रम, *इल्लम तेडि कल्वि* के प्रति ऊंचे स्तर की जागरूकता और भागीदारी को रेखांकित करता है।

यद्यपि कई स्कूल, बच्चों के मां-बाप के साथ नियमित संवाद नहीं करते हैं। बहुत कम स्कूल ही पढ़ाई में बच्चों की एक्स्ट्रा मदद (स्कूल-बाद या सप्ताहांत की कक्षाएं लेकर) कर रहे हैं। महामारी के दौरान पाठ प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले टेलीविज़न और रेडियो का उपयोग हालांकि अब भी रचनात्मक रूप से पढ़ाई में बच्चों की मदद करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनका प्रयोग पूरी तरह से बंद है।

ये सर्वे शिक्षा की आपात स्थिति पर राष्ट्रीय भागीदारी (एनसीईई) के तहत किये गये थे। इनमें प्रयुक्त प्रश्नावली, 'अ फ्यूचर ऍट स्टेक – गाइडलाइन्स फॉर स्कूल ओपनिंग' नामक प्रकाशन में स्कूलों की एक सार्थक वापसी के संदर्भ में प्रस्तुत रूपरेखा के आधार पर सुनियोजित की गयी थी।